



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-07072022-237179
CG-JK-E-07072022-237179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944

No. 351]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख

अधिसूचना

जम्मू और कश्मीर व लद्दाख, 13 जून, 2022

सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2022/01.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (ड) और 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) एतद द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन का विकास और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अक्षय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार

- इन विनियमों को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसका अनुपालन और आरईसी ढांचा कार्यान्वयन) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।
- ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- ये नियम सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे।
- ये विनियम 1 मेगावाट से अधिक के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा अन्य उपयोग करने वाले सभी वितरण लाइसेंसधारियों, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से 1 मेगावाट से अधिक की अनुबंधित मांग वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में निम्न शब्दों के अर्थ, यदि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक नहीं है, निम्नलिखित होंगे

- (क) **"अधिनियम"** का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36);
- (ख) **"आपूर्ति का क्षेत्र"** का अर्थ है वे क्षेत्र से जिनके अंदर वितरण लाइसेंसधारी/मान्य लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति के लिए अधिकृत हैं।
- (ग) **"कैप्टिव यूजर"** का वही अर्थ होगा जो विद्युत नियम 2005 के नियम 3 (2) में परिभाषित है।
- (घ) **"केंद्रीय एजेंसी"** का अर्थ है एजेंसी जिसे केंद्रीय आयोग समय-समय पर नामित कर सकता है।
- (ङ) **"केंद्रीय आयोग"** का अर्थ है अधिनियम की धारा 76 की उप धारा (1) में संदर्भित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग।
- (च) **"प्रमाणपत्र"** का अर्थ है केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र, जो अब तक संशोधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2010 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत इसके द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया जाता है।
- (छ) **"आयोग"** का अर्थ है अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (5) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग;
- (ज) **"पात्र इकाई"** का अर्थ है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण लाइसेंसधारी / डीमड लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता, जिन्हें इन विनियमों के अंतर्गत अक्षय खरीद दायित्व को पूरा करना अनिवार्य है;
- (झ) **"आधार कीमत और अधिकतम कीमत"** का अर्थ है समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2010 के अनुसार केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य, जिनके अंतर्गत ऊर्जा विनियम में केवल प्रमाणपत्रों का ही निपटारा किया जा सकता है;
- (ञ) **"जल विद्युत प्रमाणपत्र"** का अर्थ है सीईआरसी द्वारा एचपीओ दायित्व के अनुपालन की सुविधा के लिए विकसित किए जाने वाले प्रमाण पत्र।
- (ट) **"इंटरकनेक्शन सुविधाओं"** का अर्थ है वे सभी सुविधाएं जिनमें बिना किसी सीमा के, परियोजना लाइनों के लिए इनकमिंग वे के लिए स्विचिंग उपकरण, नियंत्रण, सुरक्षा और मीटरिंग डिवाइस इत्यादि शामिल हैं, जिन्हें परियोजना से विद्युत उत्पादन की निकासी को सक्षम करने के लिए उत्पादक की लागत पर इंटर-कनेक्शन बिन्दु पर स्थापित किया जाता है और रखरखाव किया जाता है;
- (ठ) **"इंटरकनेक्शन बिन्दु"** का अर्थ है वह भौतिक स्पर्श बिंदु जहां परियोजना लाइन (लाइनें) और संबन्धित उपकरण जो इंटरकनेक्शन सुविधाओं का एक हिस्सा हैं, लाइसेंसधारी की विद्युत प्रणाली से जुड़े हैं;
- (ड) **"लाइसेंसधारी"** वह व्यक्ति है जिसे लाइसेंस दिया गया है या अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लाइसेंसधारी माना जाता है;
- (ढ) **"एमएनआरई"** का अर्थ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार है;
- (ण) **"बाध्य इकाई"** का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी, एक कैप्टिव विद्युत संयंत्र का मालिक और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में एक ओपन एक्सेस उपभोक्ता, जो इन नियमों के अंतर्गत अक्षय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य है;
- (त) **"ओपन एक्सेस उपभोक्ता"** का अर्थ है वह उपभोक्ता जिसे आयोग द्वारा आपूर्ति के अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, जिसने ओपन एक्सेस प्राप्त की है या प्राप्त करने का इरादा रखता है।

- (थ) **"अधिमाम्य टैरिफ"** का अर्थ है अक्षय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर एक उत्पादन स्टेशन से ऊर्जा की बिक्री के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ
- (द) **"नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व"** का अर्थ है अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के अंतर्गत अनिवार्यता और इसे इन विनियमों के अंतर्गत बाध्य इकाई के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली खरीदने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।"
- (ध) **"नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत"** का अर्थ है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित बिजली उत्पादन स्रोत और इसमें संयुक्त विद्युत खरीद (संयुक्त विधियुत में अक्षय ऊर्जा की सीमा तक), सह-उत्पादन-आधारित विद्युत संयंत्र से उत्पन्न विद्युत शामिल है जहां गैर-जीवाश्म ईंधन उपयोग किया जाता है और जिसे एमएनआरई द्वारा नवीकरणीय स्रोतों के रूप में मान्यता प्राप्त है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- (न) **"नोडल एजेंसी"** का अर्थ है वह एजेंसी जिसे आयोग द्वारा मान्यता के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करने और केंद्रीय एजेंसी के साथ पंजीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सिफारिश करने और आयोग द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नामित किया जा सकता है।
- (त) **"वर्ष"** का अर्थ एक वित्तीय वर्ष है

"इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय आयोग द्वारा जारी अधिनियम या विनियमों या आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा की केंद्रीय आयोग इस आयोग द्वारा जारी अधिनियम या इस तरह के अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है।"

3. बाध्य इकाइयाँ

वितरण लाइसेंसधारियों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को शामिल करने वाली सभी बाध्य संस्थाओं पर विनियम 5.2 में निर्दिष्ट प्रतिशत निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगा:

- 3.1 कोई भी व्यक्ति जो 1 मेगावाट और उससे अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर आधारित ग्रिड से जुड़े कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का मालिक है, या ऐसी अन्य क्षमता जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है का मालिक है, और ऐसे संयंत्र से उत्पन्न बिजली का उपभोग करता करता है उसका प्रतिशत जीवाश्म ईंधन-आधारित कैप्टिव स्रोत के माध्यम से मांग को पूरा करने के लिए उसके उपभोग के प्रतिशत की सीमा तक आरपीओ के अधीन होगा;
- 3.2 कोई भी व्यक्ति जिसकी अनुबंध मांग 1 मेगावाट से कम की नहीं है और जो ओपन एक्सेस के माध्यम से पारंपरिक जीवाश्म ईंधन-आधारित उत्पादन से प्राप्त बिजली का उपभोग करता है, उसका प्रतिशत इस तरह के जीवाश्म ईंधन-आधारित ओपन एक्सेस स्रोत के माध्यम से उसकी खपत के प्रतिशत की सीमा तक आरपीओ के अधीन होगा।

बशर्ते कि आयोग समय-समय पर आदेश द्वारा उपरोक्त उप-खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षमता को संशोधित/परिवर्तित कर सकता है।

बशर्ते कि उप-खंड (क) के अंतर्गत शर्त स्टैंड (या आपातकालीन बैक-अप) कैप्टिव उत्पादन सुविधाओं के मामले में लागू नहीं होगी।

4. संचालन अवधि

इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट आरपीओ ढांचे की संचालन अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होगी और 31 मार्च, 2026 तक वैध होगी।

5. अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) की मात्रा

- 5.1 प्रत्येक बाध्य इकाई नवीकरणीय खरीद दायित्व के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद अपनी कुल विद्युत की खपत के एक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत की पूर्ति के लिए करेगी।

5.2 पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए आरपीओ लक्ष्य पूर्ववर्ती जेकेएसईआरसी द्वारा अपने विभिन्न आदेशों में निर्धारित किए गए थे, जिसमें जम्मू-कश्मीर बिजली अधिनियम, 2010 (निरस्त) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए अक्टूबर 2016 का आदेश शामिल है। परिभाषित न्यूनतम प्रतिशत नीचे तालिका-1 में दिए गए हैं।

तालिका -1

वर्ष	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद (किलोवाट घंटा) की न्यूनतम मात्रा (% में)		
	कुल	सौर ऊर्जा	गैर-सौर ऊर्जा
1	2	3	4
2010-11	1%	0.02%	0.98%
2011-12	3%	0.10%	2.90%
2012-13	5%	0.25%	4.75%
2013-14	5.00%	0.25%	4.75%
2014-15	6.00%	0.75%	5.25%
2015-16	7.50%	1.50%	6.00%
2016-17	7.50%	1.00%	6.50%
2017-18	8.50%	1.25%	7.25%
2018-19	9.50%	1.50%	8.00%
2019-20	10.50%	1.75%	8.75%
2020-21	11.50%	2.00%	9.50%

6. इसके बाद से, प्रत्येक बाध्य इकाई एक वर्ष के दौरान एक बाध्य इकाई के रूप में अपनी कुल खपत के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत (किलोवाट में) खरीदेगी, जैसा कि तालिका - 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2

वर्ष	सौर आरपीओ	गैर-सौर आरपीओ			कुल आरपीओ
		एचपीओ	अन्य गैर सौर आरपीओ	कुल गैर-सौर आरपीओ	
2021-22	10.50%	0.18%	10.50%	10.68%	21.18%
2022-23	10.50%	0.35%	10.50%	10.68%	21.18%
2023-24	10.50%	0.66%	10.50%	10.68%	21.18%
2024-25	10.50%	1.08%	10.50%	10.68%	21.18%
2025-26	10.50%	1.48%	10.50%	10.68%	21.18%

- 6.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्दिष्ट गैर-एचपीओ आरपीओ 2021-22 के बाद तक जारी रहेगा जब तक कि इस संबंध में आयोग द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाता है।
- 6.2 प्रत्येक बाध्य इकाई अपने स्वयं के उत्पादन के माध्यम से या अन्य स्रोतों/लाइसेंसधारियों से खरीद के माध्यम से या नवीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से या उपरोक्त विकल्पों में से किसी के संयोजन के माध्यम से अपने आरपीओ लक्ष्य को पूरा करेगी। कोई भी दीर्घकालिक खरीद व्यवस्था आयोग के अनुमोदन से ही की जाएगी। आयोग विभिन्न मामलों के आधार पर लंबी अवधि के पीपीए को मंजूरी देगा।
- 6.3 85% और उससे अधिक की सीमा तक सौर आरपीओ प्राप्त करने पर, शेष कमी, यदि कोई हो, उस विशेष वर्ष के लिए निर्दिष्ट गैर-सौर आरपीओ से अधिक खपत की गई गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की जा

सकती है। इसी प्रकार 85% और उससे अधिक अन्य गैर-सौर आरपीओ प्राप्त करने पर, शेष कमी, यदि कोई हो, को उस विशेष वर्ष के लिए निर्दिष्ट सौर आरपीओ या एचपीओ से अधिक खपत सौर या पात्र जल ऊर्जा द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा 85% और उससे अधिक की सीमा तक एचपीओ प्राप्त करने पर, शेष कमी, यदि कोई हो, को उस विशेष वर्ष के लिए अतिरिक्त सौर या अन्य गैर-सौर आरपीओ द्वारा पूरा किया जा सकता है।

7. केंद्रीय आयोग के विनियमों के अंतर्गत प्रमाण पत्र

7.1 इन विनियमों में निहित नियमों और शर्तों के अधीन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2010 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदने के लिए बाध्य संस्थाओं के लिए इन विनियमों में निर्धारित अनिवार्य दायित्वों को पूरा करने के लिए जारी प्रमाण पत्र बिजली के निर्वहन के लिए वैध दस्तावेज़ होंगे।

बशर्ते कि प्रमाण-पत्रों के क्रय द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति करने वाली बाध्य संस्था, सौर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय करने का दायित्व केवल सौर प्रमाण पत्रों के क्रय द्वारा ही पूर्ण की जायेगी तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय करने का दायित्व सौर की तुलना में गैर-सौर प्रमाणपत्रों की खरीद से पूरा किया जा सकता है।

7.2 आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अधीन, बाध्य इकाई केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2010 के अनुरूप कार्य करेगी, जिन्हें इन विनियमों के अंतर्गत नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति हेतु प्रमाण-पत्रों के खरीद के संबंध में केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

7.3 उपरोक्त उप-खंड (2.1) के अनुसार विद्युत विनियम से बाध्य संस्थाओं द्वारा खरीदे गए प्रमाण पत्र केंद्रीय आयोग/केंद्रीय एजेंसी द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार बाध्य संस्थाओं द्वारा उपयुक्त एजेंसी को जमा किए जाएंगे।

7.4 पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) आरपीओ के अनुपालन से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव करेगा। सीईआरसी एचपीओ दायित्व के अनुपालन में सहायता करेगा। एचपीओ की अनुपालना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए 8 मार्च 2019 से 31 मार्च 2021 तक विद्युत ऊर्जा की अधिकतम कीमत रु. 5.50/यूनिट प्रभावी होगी और इसके बाद उसके बाद 5% वार्षिक वृद्धि की जाएगी।

7.5 एचपीओ की पूर्ति के लिए सीईआरसी अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) तंत्र के समान उपयुक्त तंत्र पर विचार करेगा।

8. नोडल एजेंसी

8.1 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रमाणन और पंजीकरण के लिए सिफ़ारिश करने के लिए तथा इन विनियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए आयोग एक एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करेगा।

8.2 यह नोडल एजेंसी आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2010 के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं/नियमों के अनुरूप कार्य करेगी।

8.3 यह नोडल एजेंसी आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित अवधि के अंदर बाध्य संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय खरीद दायित्व के अनुपालन के संबंध में आयोग को तिमाही आधार पर स्थिति प्रस्तुत करेगी और आवश्यक होने पर नवीकरणीय खरीद दायित्व के अनुपालन के लिए आयोग को उचित कार्रवाई का सुझाव दे सकती है।

- 8.4 आयोग समय-समय पर नोडल एजेंसी को इन विनियमों के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए देय पारिश्रमिक और शुल्क को मान्यता प्राप्त संस्थाओं और बाध्य संस्थाओं से वसूल कर सकता है।
- 8.5 यदि आयोग संतुष्ट है कि राज्य एजेंसी अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने में सक्षम नहीं है, तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, और लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित कर सकती है, जैसा कि वह उपयुक्त समझती है।

9. वितरण लाइसेंसधारी

- 9.1 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार टैरिफ/वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका में आगामी वर्ष के लिए नवीकरणीय स्रोतों से खरीद की अनुमानित मात्रा को पर्याप्त प्रमाण के साथ इंगित करेगा।
- 9.2 यदि वितरण लाइसेंसधारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद की न्यूनतम मात्रा को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह इन विनियमों के विनियम 10 के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा।"

10. कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता

- 10.1 प्रत्येक कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता राज्य एजेंसी को 30 अप्रैल को या उससे पहले पिछले वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर आरपीओ की पूर्ति के लिए बिजली की कुल खपत और नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद के संबंध में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- 10.2 कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता इन विनियमों के विनियम 3 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा और/या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदेंगे या अपने स्वयं के उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, जिसे राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्रमाणीकरण के बाद ही आरपीओ उद्देश्यों के लिए माना जाएगा। यदि कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता इन विनियमों के विनियम 3 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो लक्षित मात्रा में कमी के लिए इन विनियमों के विनियम 10 के अनुसार नियामक शुल्क का भुगतान करना होगा।

11. अक्षय ऊर्जा मूल्य निर्धारण:

- 11.1 परियोजना से उत्पन्न बिजली के मूल्य निर्धारण के लिए परिचालन अवधि के दौरान शुरू की गई नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के पास निम्नलिखित का विकल्प होगा, टैरिफ मूल्य निर्धारण संरचना, जैसा कि आयोग के प्रासंगिक प्रौद्योगिकी विशिष्ट टैरिफ विनियमों (आयोग द्वारा तय परियोजना विशिष्ट टैरिफ सहित) में निर्धारित किया जा सकता है या उसे इसके लिए आरईसी तंत्र को अपनाना होगा।
- 11.2 जो परियोजना अधिमान्य टैरिफ का विकल्प चुनती है, उसे उसी टैरिफ मूल्य संरचना को जारी रखना होगा जब तक कि विद्युत खरीद समझौते की वैधता समाप्त नहीं हो जाती।
- 11.3 अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आरपीओ की सीमा तक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज से छूट दी जाएगी। तथापि, ओपन एक्सेस के माध्यम से अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आपूर्ति के लिए कोई बैंकिंग सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

नोट 1-आरईसी तंत्र में दो घटकों का मूल्य निर्धारण शामिल है, अर्थात् बिजली घटक और नवीकरणीय ऊर्जा घटक जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिचालन अवधि के प्रयोजन के लिए बिजली घटक का प्रभावी मूल्य वितरण लाइसेंसधारी की "बिजली खरीद की कुल लागत" के बराबर होगा, जबकि, आरईसी की कीमत विद्युत विनियम के आधार पर निर्धारित होगी।

नोट 2- "विद्युत खरीद की कुल लागत" वह भारित औसत जमा मूल्य है जिस पर वितरण लाइसेंसधारी पिछले वर्ष में सभी दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता से सहित बिजली खरीदेगा, जिसमें स्व-उत्पादन की लागत भी शामिल है, लेकिन अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा को छोड़कर।

नोट 3 - केंद्रीय आयोग केंद्रीय एजेंसी और नियामकों के मंच के परामर्श पर समय-समय पर सौर और गैर-सौर अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है।

12. ओपन एक्सेस के लिए प्राथमिकता:

- 12.1 स्थापित क्षमता जो भी हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली पैदा करने वाली इकाई के पास किसी भी लाइसेंसधारी की ट्रांसमिशन प्रणाली या वितरण प्रणाली या ग्रिड, जैसा भी मामला हो, के लिए ओपन एक्सेस होगी और ऐसा लाइसेंसधारी, जहां तक संभव हो, वाणिज्यिक सह-संचालन से पहले उपयुक्त इंटरकनेक्शन सुविधाएं प्रदान करेगा।
- 12.2 इंटरकनेक्शन सुविधाएं जब भी प्रदान की जाती हैं आयोग द्वारा जारी भारतीय विद्युत ग्रिड/ग्रिड कोड में निर्दिष्ट ग्रिड कनेक्टिविटी मानकों का पालन करेंगी।

13. चूक के परिणाम

यदि बाध्य इकाई किसी वर्ष के दौरान इन विनियमों में प्रदान किए गए नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा नहीं करती है और प्रमाण पत्र नहीं खरीदती है, तो आयोग बाध्य इकाई को नोडल एजेंसी द्वारा बनाए गए एक अलग फंड में जमा करने का निर्देश दे सकता है, जैसे आरपीओ की इकाइयों में कमी और केंद्रीय आयोग द्वारा तय किए गए अधिकतम मूल्य के आधार पर आयोग राशि निर्धारित कर सकता है।

जहां कोई भी बाध्य संस्था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आवश्यक न्यूनतम मात्रा में खरीद करने या अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दायित्व का पालन करने में विफल रहती है, वह आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत तय दंड के लिए उत्तरदायी होगी।

- 13.1 इस प्रकार सृजित निधि का उपयोग प्रमाण पत्र की खरीद के लिए आयोग के निर्देश के अनुसार किया जा सकता है।
- 13.2 इसके अलावा आयोग नोडल एजेंसी के एक अधिकारी को फंड के संचालन और विद्युत विनियम से फंड में राशि में से दायित्वों की पूर्ति में कमी की सीमा तक आवश्यक संख्या में प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार दे सकता है।
- 13.3 यदि बाध्य संस्थाएं आयोग द्वारा निर्देशित राशि को इस तरह के निर्देश के संचार के 15 के अंदर जमा करने में विफल रहती हैं तो इसे लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
- 13.4 नवीकरणीय खरीद दायित्व के अनुपालन में वास्तविक कठिनाई के मामले में बाध्य संस्था अगले वर्ष अनुपालन आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है। हालांकि, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा खरीद के लिए क्रेडिट अगले वर्ष में समायोजित नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी है, वहाँ इस विनियम के पहले पैराग्राफ में उल्लिखित दंड का प्रावधान या अधिनियम की धारा 142 के प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा।

बशर्ते आगे कि यदि बाध्य इकाई लाइसेंसधारी / संभावित लाइसेंसधारी है, तो उस इकाई पर आयोग द्वारा लागू दंड कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में नहीं जोड़ा जाएगा।

14. आदेश जारी करना और अभ्यास निर्देश

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है;

15. छूट की शक्ति

आयोग लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ आदेश द्वारा, और प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इन विनियमों के प्रावधानों में स्वयं पर या एक व्यक्ति द्वारा इसके सम्मुख किए गए आवेदन पर छूट प्रदान कर सकता है, ऐसे व्यक्ति में कोई कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्तियों का संघ या निकाय शामिल है, चाहे वह कॉर्पोरेट हो या नहीं हो।

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- 16.1 इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, आयोग आदेश द्वारा किसी भी उत्पादन कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उचित निर्देश जारी कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होगा और जो आयोग को कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या लाभप्रद प्रतीत होता है।
- 16.2 कोई भी उत्पादन कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता, ओपन एक्सेस उपभोक्ता आयोग को आवेदन कर सकते हैं और इन विनियमों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

17. संशोधन करने की शक्ति

आयोग, किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, संशोधित कर सकता है या निरस्त कर सकता है।

18. अपवाद

- 18.1 इन विनियमों में कुछ भी जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकता है, को आयोग की निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।
- 18.2 इन विनियमों में कुछ भी जो प्रावधानों या इन विनियमों से भिन्न है, आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया को अपनाने से नहीं रोकेगा, यदि आयोग एक मामले या मामलों के एक समूह की विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से और लिखित कारणों से ऐसे मामलों से निपटने के लिए आवश्यक या लाभकारी है समझता है।
- 18.3 इन विनियमों में कुछ भी जिसके लिए विनियम नहीं बनाए गए हैं, आयोग को किसी भी मामले से निपटने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के अंतर्गत प्रदान की गई किसी भी शक्ति को प्रयोग करने के लिए व्यक्त या अव्यक्त रूप से नहीं रोकेगा, और आयोग इस प्रकार के मामलों, शक्तियों और कार्यों से अपने विवेक के अनुसार निपट सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा!

स्थान: जम्मू

वी. के. धार, सचिव,

दिनांक:

[विज्ञापन III/4/असा./158/2022-23]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, JAMMU & KASHMIR AND LADAKH NOTIFICATION

Jammu & Kashmir and Ladakh, the 13th June, 2022

No. JERC-JKL/REG/2022/01.—In exercise of powers conferred under sections 86 (1) (e) and 181 of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling it in this behalf, Joint Electricity Regulatory Commission (for the Union Territories J&K and Ladakh) hereby makes the following regulations for the development of power generation from renewable energy sources and for procurement of energy from renewable sources by distribution licensee.

1. Short title, commencement and extent of application

- (i) These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories Jammu & Kashmir and Ladakh (Renewable Purchase Obligation, its Compliance and REC framework Implementation) Regulations, 2022.

- (ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.
- (iii) These regulations shall apply to the whole of the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.
- (iv) These Regulations shall apply to all Distribution Licensees, captive users, using other than Renewable Energy Sources exceeding 1 MW, and to Open Access Consumers with a contracted demand exceeding 1 MW from sources other than Renewable sources of Energy.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "**Act**" means the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003);
- (b) "**Area of Supply**" means the areas within which the Distribution Licensees/ deemed licensees are authorized to supply electricity.
- (c) "**Captive User**" shall have the same meaning as defined in rule 3 (2) of Electricity Rules 2005.
- (d) "**Central Agency**" means the agency, as the Central Commission may designate from time to time.
- (e) "**Central Commission**" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub section (1) of section 76 of the Act.
- (f) "**Certificate**" means the Renewable Energy Certificate issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed by it under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations 2010 as amended till date;
- (g) "**Commission**" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territories of J&K and Ladakh constituted by the Central Government under sub-section (5) of section 83 of the Act;
- (h) "**Eligible Entity**" means the Distribution Licensees/ deemed licensees, captive user (s) and open access consumer (s) in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, which is mandated to fulfill Renewable Purchase Obligation under these Regulations;
- (i) "**Floor Price and Forbearance Price**" means the minimum price and the ceiling price, respectively as determined by the Central Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulations 2010, as amended from time to time, within which only the certificates can be dealt in the power exchange;
- (j) "**Hydro Energy Certificate**" means certificates to be developed by CERC to facilitate compliance of HPO obligation.
- (k) "**Interconnection facilities**" means all the facilities which shall include, without limitation, switching equipment, control, protection and metering devices etc. for the incoming bay (s) for the project line(s), to be installed and maintained by the licensee at the Inter-Connection Point at the cost of the generator to enable evacuation of electrical output from the Project;
- (l) "**Interconnection point**" means the physical touch point where the project line(s) and the allied equipment forming a part of the interconnection facilities are connected to the licensee's power system;
- (m) "**Licensee**" means a person who is granted a license or is a deemed licensee under section 14 of the Act;
- (n) "**MNRE**" means the Ministry of New and Renewable Energy, GoI;
- (o) "**Obligated Entity**" means the distribution licensee, a consumer owning a captive power plant and an open access consumer in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, which is mandated to fulfill renewable purchase obligation under these regulations;

- (p) **“Open access Consumer”** means a Consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person other than the Distribution Licensees of his area of supply who has availed of or intends to avail of open access
- (q) **“Preferential Tariff”** means the tariff fixed by the Commission for sale of energy from a generating station based on renewable energy sources
- (r) **“Renewable Energy Purchase Obligation”** means quantum as mandated under clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Act and specified under these Regulations for the obligated entity to purchase electricity generated from renewable energy sources.”
- (s) **“Renewable Energy Sources”** means Electricity generating sources recognized or approved by the Ministry of New and Renewable Energy and includes bundled power purchase (to the extent of Renewable Energy content in the bundled Power), power generated from co-generation-based power plants wherein the fuel used is non-fossil fuel duly recognized as renewable sources by MNRE and certified by the State accredited agency.
- (t) **“Nodal Agency”** means the agency as may be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration with Central Agency and to undertake such functions as may be assigned by the Commission.
- (u) **“Year”** means a financial year

“Words and expressions used in these Regulations and not expressly defined herein but defined in the Act or the regulations issued by the Central Commission or any other regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or such other regulations issued by the Central Commission or such other regulations issued by the Commission.”.

3. Obligated Entities

The percentage specified in Regulation 5.2 shall be applicable to all Obligated Entities covering Distribution Licensees, Open Access Consumers and captive users within UTs of J&K and Ladakh, subject to the following conditions:

- 3.1 Any person who owns a grid-connected Captive Generating Plant based on conventional fossil fuel with installed capacity of 1 MW and above, or such other capacity as may be stipulated by the Commission from time to time, and consumes electricity generated from such Plant for his own use shall be subject to RPO to the extent of a percentage of his consumption met through such fossil fuel-based captive source;
- 3.2 Any person having a Contract Demand of not less than 1MW and who consumes electricity procured from conventional fossil fuel-based generation through Open Access shall be subject to RPO to the extent of a percentage of his consumption met through such fossil fuel-based Open Access source:

Provided that the Commission may, by order, modify/revise the minimum capacity referred to in sub-clauses (a) and (b) above from time to time.

Provided further that the condition under sub-clause (a) above shall not be applicable in case of stand-by (or emergency back-up) captive generating facilities.

4. Operating Period

The Operating Period of the RPO framework specified under these Regulations shall commence from the FY 2021-22 and shall be valid until 31 March, 2026.

5. Quantum of Renewable Purchase Obligation (RPO)

- 5.1 Every obligated entity shall purchase electricity from renewable energy sources for fulfillment of a defined minimum percentage of its total consumption of electricity under the Renewable Purchase Obligation.
- 5.2 RPO targets for erstwhile Jammu and Kashmir State were fixed by erstwhile JKSERC in its various orders including order of October 2016 for 2nd Control Period FY 2016-17 to FY 2020-21 under the J&K Electricity Act, 2010 (Repealed). The defined minimum percentages are given below in the Table– 1.

Table – 1

Year	Minimum quantum of purchase(in %) from renewable energy sources (in kWh)		
	Total	Solar	Non-Solar
1	2	3	4
2010-11	1%	0.02%	0.98%
2011-12	3%	0.10%	2.90%
2012-13	5%	0.25%	4.75%
2013-14	5.00%	0.25%	4.75%
2014-15	6.00%	0.75%	5.25%
2015-16	7.50%	1.50%	6.00%
2016-17	7.50%	1.00%	6.50%
2017-18	8.50%	1.25%	7.25%
2018-19	9.50%	1.50%	8.00%
2019-20	10.50%	1.75%	8.75%
2020-21	11.50%	2.00%	9.50%

6. Henceforth, every Obligated Entity shall purchase electricity (in kWh) from renewable energy sources, at a defined minimum percentage of its total consumption as an Obligated Entity during a year shown as under in the Table – 2.

Table -2

Year	Solar RPO	Non-Solar RPO			Total RPO
		HPO	Other Non-solar RPO	Total Non-solar RPO	
2021-22	10.50%	0.18%	10.50%	10.68%	21.18%
2022-23	10.50%	0.35%	10.50%	10.68%	21.18%
2023-24	10.50%	0.66%	10.50%	10.68%	21.18%
2024-25	10.50%	1.08%	10.50%	10.68%	21.18%
2025-26	10.50%	1.48%	10.50%	10.68%	21.18%

- 6.1 The Non-HPO RPO specified in the financial year 2021-22 shall be continued beyond 2021-22 till any revision is affected by the Commission in this regard.
- 6.2 Every obligated entity shall meet its RPO target by way of its own generation or by way of purchase from other sources / licensees or by way of purchase of Renewal Energy Certificates or by way of combination of any of the above options. Any long-term purchase arrangements shall be made only with the approval of the Commission. The Commission shall approve long term PPAs on case-to-case basis.
- 6.3 On achieving of solar RPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess non-solar renewable energy consumed beyond specified non-solar RPO for that particular year. Similarly on achievement of other non-solar RPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess solar or eligible hydro energy consumed beyond specified solar RPO or HPO for that particular year. Further on achievement of HPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess solar or other non-solar RPO for that particular year.

7. Certificates under the Regulations of the Central Commission

- 7.1 Subject to the terms and conditions contained in these regulations the Certificates issued under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 shall be the valid instruments for the discharge of the mandatory obligations set out in these regulations for the obligated entities to purchase electricity from renewable energy sources.

Provided that obligated entity fulfilling the renewable purchase obligation by purchase of certificates, the obligation to purchase electricity from generation based on solar renewable energy source shall be fulfilled by purchase of solar certificates only, and the obligation to purchase electricity from generation based on renewable energy other than solar can be fulfilled by purchase of non –solar certificates.

- 7.2 Subject to such direction as the Commission may give from time to time, the obligated entity shall act consistent with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 notified by the Central Commission in regard to the procurement of the certificates for fulfillment of the Renewable Purchase Obligation under these regulations.
- 7.3 The Certificates purchased by the obligated entities from the power exchange in accordance with sub -clause (2.1) above shall be deposited by the obligated entities to the appropriate agency in accordance with the detailed procedure to be issued by the Central Commission/ Central Agency.
- 7.4 Power System Operation Corporation Limited (POSOCO) shall maintain data related to compliance of RPOs. CERC to facilitate compliance of HPO obligation, would have a capping price of Rs 5.50/ unit of electrical energy w.e.f. 8th March 2019 to 31st March 2021 and with annual escalation @5% thereafter for purpose of ensuring HPO compliance.
- 7.5 CERC shall consider to device suitable mechanism similar to Renewable Energy Certificates (REC) mechanism to facilitate fulfillment of HPO.

8. Nodal Agency

- 8.1 The Commission shall designate an agency as Nodal Agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake functions under these regulations.
- 8.2 The Nodal Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission and shall act in consistent with the procedures/rules laid by Central Agency for discharge of its functions under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010.
- 8.3 The Nodal Agency shall submit quarterly status to the Commission in respect of compliance of renewable purchase obligation by the obligated entities in the format and within the period as stipulated by the Commission and may suggest appropriate action to the Commission if required for compliance of the renewable purchase obligation.
- 8.4 The Commission may from time to time fix the remuneration and charges payable to the Nodal Agency for discharge of its functions under these regulations to be recovered from the accredited entities and obligated entities.
- 8.5 If the Commission is satisfied that the State Agency is not able to discharge its functions satisfactorily, it may by general or special order, and by recording reasons in writing, designate any other agency to function as Nodal Agency as it considers appropriate.

9. Distribution Licensee:

- 9.1 Each distribution licensee shall indicate along with sufficient proof thereof, the estimated quantum of purchase from renewable sources for the ensuing year in Tariff /Annual Revenue Requirement (ARR) petition in accordance with the regulations notified by the Commission.

- 9.2 If the Distribution Licensee fails to fulfill the minimum quantum of purchase from renewable energy sources, it shall be liable for penalty as per Regulation 10 of these Regulations.”

10. Captive User (s) and Open Access Consumer (s):

- 10.1 Every Captive User and Open Access Consumer shall submit necessary details regarding total consumption of electricity and purchase of energy from renewable sources for fulfillment of RPO on yearly basis on or before 30th April to the State Agency for the previous year.
- 10.2 Captive User(s) and Open Access Consumer(s) shall purchase renewable energy and/ or Renewable Energy Certificate (s) as stated in Regulation 3 of these Regulations or generate renewable energy for its own consumption, which shall be considered for RPO purposes only after certification by the State Nodal Agency. If the Captive User(s) and Open Access consumer (s) are unable to fulfill the criteria as specified in Regulation 3 of these Regulations, the short fall of the targeted quantum would attract payment of regulatory charge as per Regulation 10 of these Regulations.

11. Renewable Energy Pricing:

- 11.1 New Renewable Energy Projects commissioned during the operative period shall have an option of following, either the tariff pricing structure, as may be stipulated in the relevant technology specific tariff Regulations of the Commission (including project specific tariff decided by the Commission) or adopt the REC mechanism for pricing of the electricity generated from the project.
- 11.2 Project which opts for preferential tariff shall have to continue with the same tariff pricing structure until the validity of Power Purchase Agreement ceases.
- 11.3 Open access consumer receiving electricity from renewable energy sources shall be exempted from the cross-subsidy surcharge determined by the Commission from time to time to the extent of RPO. However, no banking facility shall be provided for supply of electricity from renewable energy sources through open access

Note 1—The REC mechanism entails pricing of two components, namely, electricity component and renewable energy component representing environmental attributes of renewable energy generation. For the purpose of the operating period, the effective electricity component price shall be equivalent to “Pooled Cost of power purchase “of the Distribution Licensee, whereas, the price of RECs shall be as discovered in the Power Exchange.

Note 2- “Pooled Cost of Power Purchase” is the weighted average pooled price at which the Distribution Licensee shall purchase the electricity including cost of self-generation, if any, in the previous year from all the long-term and short-term energy suppliers, but excluding those based on renewable energy sources.

Note 3 – The Central Commission, in consultation with the Central Agency and the Forum of Regulators, from time to time prescribes the Floor Price and the Forbearance Price separately for solar and non-solar Renewable Energy Certificate(s).

12. Priority for Open Access:

- 12.1 An entity generating electricity from renewable energy sources irrespective of installed capacity shall have open access to any licensee’s transmission system or distribution system or grid, as the case may be, and such a licensee shall provide appropriate interconnection facilities, as far as possible, before commercial operation co
- 12.2 The interconnection facilities, whenever provided, shall follow the grid connectivity standards as specified in the Indian Electricity Grid/ Grid Code issued by the Commission.”

13. Consequences of default

If the obligated entity does not fulfill the renewable purchase obligation as provided in these regulations during any year and does not purchase the certificates, the Commission may direct the obligated entity to deposit into a separate fund, to be created and maintained by Nodal Agency, such amount as the Commission may determine on the basis of the shortfall in units of RPO and the forbearance price decided by Central Commission.

Where any obligated entity fails to comply with the obligation to purchase the required minimum quantum of purchase from renewable energy sources or procure the Renewable Energy Certificate (s), it shall also be liable for penalty as may be decided by the Commission under Section 142 of the Act.

- 13.1 That the fund so created shall be utilized as may be directed by the Commission for purchase of the certificates.
- 13.2 Further that the Commission may empower an officer of the Nodal Agency to operate the fund and procure from the Power Exchange the required number of certificates to the extent of the shortfall in the fulfillment of the obligations, out of the amount in the fund.
- 13.3 That the obligated entities shall be in breach of its license condition if it fails to deposit the amount directed by the Commission within 15 days of the communication of such direction.
- 13.4 That in case of genuine difficulty in complying with a Renewable Purchase Obligation the obligated entity can approach the Commission for carry forward of compliance requirement to the next year. However, credit for excess renewable energy purchase would not be adjusted in the next year.

Provided that where the Commission has consented to the carry forward of compliance requirement, the provision of penalty as mentioned in the first paragraph of this Regulation or the provision of section 142 of the Act shall not be invoked.

Provided further that the penalty enforced by the Commission on the obligated entity shall not be a pass through in the Aggregate Revenue Requirement (ARR) in case the obligated entity is the licensee/ deemed licensee.

14. Issue of Orders and Practice Directions

Subject to the provisions of the Act, the Commission may issue Orders and Practice Directions with regard to the implementation of these Regulations;

15. Power to Relax:

The Commission may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of being heard to the parties affected or likely to be affected, relax any of the provisions of these Regulations on its own or on an application made before it by a person which includes any company or body corporate or association or body of individuals whether corporate or not.

16. Power to remove difficulties

16.1 In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by order, issue appropriate directions to any generating company, Distribution Licensee, captive user and open access consumer, to take suitable action, not being inconsistent with the provision of the Act, which appear to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

16.2 Any generating company, Distribution Licensees, captive user, open access consumers may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulty that may arise in implementation of these Regulations.

17. Power to amend

The Commission, may, at any time, vary, alter, modify or repeal any provisions of these Regulations.

18. Savings

- 18.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Commission.
- 18.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

- 18.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission.

Place : Jammu

V. K. DHAR, Secy.

Date:

[ADVT.-III/4/Exty./158/2022-23]